



नई दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की बैठक के मौके पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य।

वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए पूरा प्रयास: योगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। उन्होंने एमएसएमई, महिला सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीएम गति शक्ति, स्वास्थ्य एवं पोषण पर चरणवार यूपी की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के देश को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प में योगदान देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।

यूपी में रूल ऑफ लॉ की हुई है स्थापना: सीएम योगी ने कहा कि 'रूल ऑफ लॉ' की स्थापना से देश-विदेश में प्रदेश का पर्सेप्शन बदला है। इसके लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी। प्रदेश सरकार की

प्रधानमंत्री को महाकुंभ 2025 में किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीजी इण्डिया इण्डेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश फ्रण्ट रनर कैटेगरी में सम्मिलित हो गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक प्रदेश की 351 बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्तमान में नीति आयोग के 'नीति फॉर स्टेट्स पोर्टल' पर अपलोड हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी जनवरी, 2025 में प्रयागराज महाकुम्भ में आमंत्रित करते हुए कहा कि 12 वर्ष के अन्तराल पर यह पावन अवसर आता है। राज्य सरकार महाकुम्भ-2025 के स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। सभी तैयारियां पूर्ण होने की ओर हैं।

सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि एनसीआरबी के आंकड़े भी करते हैं। इसके अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है, जो जेल के बाहर स्वच्छन्द विचरण कर रहा हो। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस बल का निरन्तर मॉडर्नाइजेशन, नई तकनीकी व नये इक्विपमेंट्स के जरिये किया जा रहा है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम

थाना स्थापित किया गया है। प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क क्रियाशील की गई है।

उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। व्यापक जनसहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों यथा-स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, वृहद वृक्षारोपण जन अभियान, मातृभूमि योजना आदि को क्रियान्वित किया जा रहा है।

'हिमालयी राज्यों की खास नीतियां बनें'

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उत्तराखंड निरन्तर काम कर रहा है। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया है। पेयजल संकट के समाधान के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन ऑथोरिटी का गठन किया है, जो जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की परियोजना पर कार्य कर रही है।